



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



सब नागरिक समान सबको सम्मान

समानता और न्याय की
भावना को समर्पित

मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् बैठक

अध्यक्षता

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

19 जुलाई 2026

जगदीशपुर, जिला भोपाल



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार सभी वर्गों के साथ संतुलन बनाते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश की जनहितैषी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

समान नागरिक संहिता



सभी जाति, धर्म या वर्ग के नागरिकों
के लिए एक समान कानून
सुनिश्चित होंगे



सभी पारंपरिक सांस्कृतिक विविधताएं,
धार्मिक रीति-रिवाज पूरी
तरह सुरक्षित होंगे



विवाह, तलाक, भरणपोषण, उत्तराधिकार
जैसे मामलों में अब सभी को एक समान
कानूनी सुरक्षा मिलेगी



जुबानी, एकतरफा और अनौपचारिक
तलाक पूरी तरह गैर-कानूनी
और दंडनीय होंगे



बहुविवाह पर पूरी तरह रोक एवं विवाह
और तलाक पर पंजीयन
अनिवार्य होगा



लिव-इन रिलेशनशिप का
पंजीयन अनिवार्य



माता-पिता की वैवाहिक स्थिति से परे सामान्य
बच्चों की तरह जैविक, दत्तक, सेरोगेसी या
एआरटी से जन्मे बच्चों को समान
कानूनी मान्यता



जनजातीय संस्कृति और जीवन शैली का सम्मान
करते हुए प्रदेश की भील, गोंड, कोरकू, बैगा,
सहरिया और भारिया जैसी जनजातियों पर
यह कानून लागू नहीं होगा

अमेरिका का लगातार सातवीं रात ईरान पर भीषण हमला

एजेसी►►तेहरान/वॉशिंगटन

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि उसने लगातार सातवीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों, हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं पर हमले किए। इन हमलों में सीरिक, बुशेहर, बंदर अब्बास, केशम द्वीप और यज्द को निशाना बनाया गया।

वहीं, ईरानी सांसद अहमद बख्यायेश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट में दो तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। आईआरजीसी ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइंस से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। हालांकि, सेंटकॉम) ने इस दावे को झूठा बताया।

समुद्र में बिछी माइंस से टकराने के बाद दो तेल टैंकरों में लगी आग



अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त ईरान में बंदर अब्बास-रुदान पुल

ईरानी सांसद अहमद बख्यायेश अर्देस्तानी ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने जमीनी हमला किया, तो ईरान कुवैत और बहरीन में घुस जाएगा और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर देगा

ईरान का समझौते से पीछे हटने का ऐलान

ईरान ने अमेरिका के साथ एक महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने का ऐलान किया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका ने खुद समझौते का उल्लंघन किया, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हुआ युद्धविराम अब खत्म हो चुका है।



कुवैत में आग लगने से कई यूनिट बंद

कुवैत के बिजली, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि ईरान के ताजा हमलों के बाद एक बिजली और समुद्री जल विलक्पीकरण (डिसेलिनेशन) संयंत्र के एक हिस्से में आग लग गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर बिजली उत्पादन की कई यूनिटों को बंद कर दिया गया।

ताबूत में ट्रंप की फैमिली लिखा- 'खून के बदले खून'



ईरान ने राजधानी तेहरान में एक नया होर्डिंग लगाया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके पूरे परिवार को ताबूतों में दिखाया गया है। इन ताबूतों पर अमेरिकी झंडा लिपटा हुआ है, जबकि पीछे व्हाइट हाउस को आग की लपटों में धरा दिखाया गया है। होर्डिंग में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया और उनके पांचों बच्चों की तस्वीरें भी हैं। इस पर फारसी भाषा में 'खून के बदले खून' का नारा लिखा गया है।

ईरान के 20 गांवों में पानी संकट

ईरान के जस्क काउंटी के बुंजी तटीय गांव में समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले सिस्टम पर अमेरिकी हमले के बाद 20 गांवों के करीब 10 हजार लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। होमोजगान वाटर और वेस्टवाटर कंपनी के प्रमुख हमजेह पूर ने कहा कि हमले में समुद्र से पानी खींचने वाला पंपिंग स्टेशन और बुंजी के डिसेलिनेशन प्लांट का पावर ट्रांसफॉर्मर पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्होंने इन हमलों को अपराध और आतंकवादी हमला बताया।

अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने कुवैत के अल-अहमदी बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के ईंधन आपूर्ति पियर और बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। बहरीन में अमेरिकी खुफिया डेटा सेंटर 'बटेल्को' और कुवैत में अमेरिकी सिमल एवं दूरसंचार केंद्र को भी नष्ट कर दिया गया।

खबर संक्षेप

यूक्रेनी ड्रोन हमले में 7 रूसी लोगों की मौत

मास्को। रूस में रात में यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई और 51 अन्य घायल हो गए।



रूसी अधिकारियों के अनुसार, यूक्रेनी ड्रोन ने रात में रूस की प्रमुख ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्डबेरीज के दो बड़े गोदामों को निशाना बनाया। इनमें से एक यूक्रेन की सीमा से लगभग 360 किमी दूर तांबोव क्षेत्र के कोतोव्स्क कस्बे में और दूसरा मास्को से लगभग 50 किमी पूर्व स्थित इलेक्ट्रोस्टाल शहर में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की ने भी इसकी पुष्टि की है।

नॉर्वे में भीषण आग से 100 घर जलकर खाक

ड्रामेन। दक्षिणी नॉर्वे में लगी भीषण आग में 100 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। सैकड़ों लोगों को यहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे ड्रामेन शहर में एक इमारत में आग लगी और देखते ही देखते आसपास के इलाके और नजदीकी जंगलों तक फैल गई। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह भी दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे रहे।

चीन में भूस्खलन से 8 की मौत, बचाव कार्य जारी

चोंगकिंग। दक्षिण-पश्चिमी चीन के चोंगकिंग शहर में हुए भूस्खलन में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य लापता हैं। बचाव दल शनिवार को जीवित बचे लोगों की तलाश में अभियान चला रहा है। यह भूस्खलन शुक्रवार सुबह चोंगकिंग नगर पालिका के बाहरी क्षेत्र स्थित पेंगशुई काउंटी में हुआ, जब बड़ी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी ढलान से नीचे खिसक गई और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं।

पीओके में हो रही हिंसा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घिरा पाक

यूएन मानवाधिकार ने जताई चिंता, मौतों की त्वरित, गहन और निष्पक्ष जांच की भी मांग

एजेसी►►न्यूयॉर्क

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में जारी अशांति को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (ओएचसीएचआर) ने गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों, दोनों पक्षों में हुई मौतों की परिस्थितियों की पाददर्शी जांच कराने की मांग की है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। जिनेवा से जारी बयान में



ओएचसीएचआर ने कहा कि 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकांश प्रदर्शनकारी हैं, जबकि कुछ कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

‘फोर्सेस फर्स्ट कॉन्वलेव’ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले

आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ केवल एक बयान नहीं, सरकार की कार्यशैली

राजनाथ सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे जटिल अभियान की सफलता में भारत के बदले हुए रक्षा क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही। इस अभियान के दौरान आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा भारत

आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर ध्यान

भारतीय सैनिक राष्ट्र गौरव का प्रतीक

राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमाओं पर तैनात सैनिक, समुद्र की गहराइयों में देश की सुरक्षा कर रहे नौसैनिक और आकाश में राष्ट्र की रक्षा करने वाले वायु योद्धा भारत के राष्ट्रिय गौरव के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जो देश अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं जानता, उसका मविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे जटिल अभियान की सफलता में भारत के बदले हुए रक्षा क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस जैसी उन्नत प्रणालियों के साथ कई अन्य अत्याधुनिक उपकरणों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया।

रक्षा औद्योगिक गलियारे में 70 हजार करोड़ का निवेश

रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा सुधार है। इन गलियारों में उन्नत रक्षा विनिर्माण का काम हो रहा है और कई कंपनियां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन चुकी हैं। इन दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारों में लगभग 70 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है, जिनमें से करीब 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है।

12 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए

उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 'राष्ट्र सर्वोपरि' और 'सेना सर्वोपरि' की भावना के साथ रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं।

सीसीपीए का स्पाइसजेट पर एक्शन

डार्क पैटर्न अपनाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना, जांच में दोषी



एजेसी►►नई दिल्ली

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर 'डार्क पैटर्न' (भ्रामक डिजाइन प्रथाओं) का इस्तेमाल करने के मामले में स्पाइसजेट लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की ये

प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(9) और डार्क पैटर्न्स की रोकथाम एवं विनियमन संबंधी दिशानिर्देश, 2023 का उल्लंघन हैं। सीसीपीए की अध्यक्ष मुख्य आयुक्त स्मति निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई में हुई जांच में पाया गया कि स्पाइसजेट अपने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर पहले से टिक किए गए चेकबॉक्स के जरिए उपभोक्ताओं को स्वतः 'स्पाइसक्लब' लॉयल्टी प्रोग्राम में नामांकित कर रही थी।

टाइगर हिल अभियान: वीरता का सम्मान



मिलिट्री टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने बास के रिविल प्रशासन के साथ मिलकर, 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर 'टाइगर हिल अभियान 2026' को सफलतापूर्वक आयोजित किया। बास के जिला मुख्यालय बनने के बाद यह अपनी तरह की पहली पहल थी। इस अभियान ने कारगिल युद्ध की विरासत को संजोते हुए मिलिट्री टूरिज्म को बढ़ावा दिया। इसमें वाकमेट डिग्री कॉलेज, बास के ग्यारह प्रशिक्षित टूर और ट्रेक गाइड भी शामिल हुए।

पीयूष गोयल ने फिनलैंड की प्रमुख कंपनियों से की मुलाकात

दूरसंचार, निवेश सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी और मजबूत करने पर जोर

वीटीटी के साथ नवाचार पर जोर

यूरोप के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में शामिल वीटीटी तकनीकी अनुसंधान केंद्र में हुई बैठक के दौरान अनुसंधान, नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकी, औद्योगिक परिवर्तन, उन्नत सामग्री, डिजिटलीकरण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अनुसंधान साझेदारी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को मजबूत करने की संभावनाओं पर भी विचार किया।

केओएनई के साथ स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा

केओएनई कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में स्मार्ट शहरी अवसंरचना, लिफ्ट और एस्केलेटर तकनीक, सतत निर्माण समाधान, उन्नत विनिर्माण और स्थानीयकरण पर सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की गई। भारत के तेजी से विकसित हो रहे अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी विचार हुआ।

केम्पी समूह के साथ औद्योगिक नवाचार पर फोकस

केम्पी समूह के नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उन्नत औद्योगिक मशीनरी, वोल्टेज तकनीक, विनिर्माण नवाचार, आधुनिक औद्योगिक समाधान और भारत के बढ़ते विनिर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं भी तलाशी गईं।

भारत-फिनलैंड आर्थिक संबंधों को मिली नई गति

इन बैठकों ने फिनलैंड के उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर प्रदान किया, जिससे भारत की विदेशीकरण विनिर्माण और नवाचार साझेदार के रूप में पहचान और मजबूत हुई। यह दौरा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, सतत विनिर्माण और निवेश के क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी को नई गति देने की साझा प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉ. सिंह ने दतिया में किया मीडिया एवं सोशल मीडिया सेंटर का उद्घाटन

हरिभूमि न्यूज ►► गोपाल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने शुक्रवार को दतिया उपचुनाव के लिए होटल प्राक्षी में बनाए गए मीडिया एवं सोशल मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बैठक को संबोधित किया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए स्थापित मीडिया एवं सोशल मीडिया सेंटर संगठन, मीडिया और जनता के बीच प्रभावी संवाद, समन्वय तथा तथ्यपरक सूचना के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यालय का उद्घाटन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक, पारदर्शी और

►► **सूचना और विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम है मीडिया व सोशल मीडिया: हेमंत**

प्रभावी संवाद तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आज के डिजिटल युग में मीडिया और सोशल मीडिया जनसंचार के सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुके हैं।

तकनीक ने सूचनाओं के प्रसार को तेज और व्यापक बनाया है, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में सत्य, तथ्य और विश्वसनीय जानकारी को समाज तक पहुंचाना हम



प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते खंडेलवाल। साथ में उपस्थित डॉ. सिंह व अग्रवाल।

सभी की साझा जिम्मेदारी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल ने उपस्थित पत्रकारों एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रदेश सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी, पार्टी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी बृजगोपाल लोया, राजलखन सिंह एवं सोशल मीडिया संभाग प्रभारी आयुष सुरेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

हम सभी कार्यकर्ता एक विचार और एक उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। हमें संगठन को निरंतर मजबूत बनाना है। यह बात भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, वरिष्ठ नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा, उपचुनाव प्रभारी भारत सिंह कुशवाह, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने होटल रतन रॉयल में बनाए गए दतिया उपचुनाव कार्यालय का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।



►► **भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता को अवसर मिला है: खंडेलवाल**

खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा विचारधारा और कार्यकर्ताओं का संगठन है। भाजपा में एक सामान्य कार्यकर्ता को अपनी मेहनत और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिला है।

►► **भाजपा सरकारों ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया: डॉ. सिंह**

भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकारों ने भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन के साथ विकसित भारत की मजबूत नींव रखने का कार्य किया है।

खबर संक्षेप



गुरुनानक टेकरी द्वार एवं सड़क का किया लोकार्पण

भोपाल। सांसार आलोक शर्मा व महापौर मालती राय ने शुक्रवार को ईदगाह हिल्स क्षेत्र में बने श्री गुरुनानक टेकरी द्वार एवं सड़क का लोकार्पण किया। गुरुनानक टेकरी द्वार एवं सड़क निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद सरोज आसरी के अलावा नेहा बग्गा, राकेश कुकरेजा, यतेंद्र मकवाना, विक्रम सिंह, पम्मी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं गुरुद्वारा गुरुनानक टेकरी प्रबंध समिति के सदस्यगण मौजूद थे।

महापौर ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन



भोपाल। महापौर मालती राय ने शुक्रवार को साईं बाबा नगर में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। यहां करीब 14 लाख रुपए की लागत से सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जा रहा है।

बुंदेली शेफ सीजन 4 में 7 प्रतिभागी पहुंचे क्वार्टर फाइनल में

छतरपुर। ऑनलाइन कुकिंग प्रतियोगिता 'बुंदेली शेफ सीजन 4' के हाल ही में आयोजित दूसरे ऑडिशन का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमे 7 प्रतिभागियों ने जगह बनाई है। दूसरे ऑडिशन में कुल 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से दीक्षा पटेल, किरण लाल, नाजमी अख्तर, ऋतिका शर्मा, रुचि जैन, सुरुचि जैन और वरीशा नियाजी आगे बढ़ी। इन प्रतिभागियों ने बुंदेलखंड की पारंपरिक रेसिपीज को अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया। पहले और दूसरे ऑडिशन से चर्चित सभी प्रतिभागियों का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में होगा। इसके बाद चर्यनित प सेमी फाइनल और अंततः अग्रस्त के अंत में आयोजित होने वाले भव्य ग्रैंड फिनले तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। बुंदेली शेफ सीजन 4 का तीसरा और अंतिम ऑडिशन 20 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।

बुंदेलखंड के किसानों ने पानी का अभाव झेला, हम इसे बनाएंगे समृद्ध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा-टीकमगढ़ में बनेगा सर्व सुविधायुक्त मेडिकल कॉलेज

विशेष प्रतिनिधि ►► गोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है बुंदेलखंड के किसानों ने पानी के अभाव में गरीबी झेली और कई कठिनाइयां उठाईं। लेकिन अब हम केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के जरिए बुंदेलखंड को समृद्ध बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। परियोजना पूरी होने पर यह क्षेत्र खेती के मामले में पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस विशाल परियोजना से टीकमगढ़ जिले की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी, जिससे किसानों के खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचेगा और उनकी आय में ऐतिहासिक वृद्धि होगी।

डॉ. यादव शुक्रवार को टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जिले को 189 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें 102.45 करोड़ रुपए के 33 कामों का लोकार्पण और 86.66 करोड़ रुपए के 39 कामों का भूमिपूजन शामिल है। डॉ. यादव ने घोषणा की कि टीकमगढ़ में सर्वसुविधायुक्त भव्य मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इसका भूमिपूजन भी शीघ्र ही किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

►► **189 करोड़ के 72 विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन**



आयोजन को संबोधित करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन। दूसरी फोटो में उपस्थित नागरिक।

►► **विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी किए वितरित**



एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि टीकमगढ़ जिले के जतारा और बड़ागांव धसान में सर्वसुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालय भवनों और सोलह विद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के नव-निर्माण कार्यों का उद्घाटन मिला है। युवाओं और खिलाड़ियों के लिए हॉकी सिंथेटिक एस्ट्रोर्टफ स्टेडियम और बास्केटबॉल कोर्ट का भी लोकार्पण हुआ है। खरगापुर में 40 करोड़ रुपए से बनने वाले नए सांदीपनि विद्यालय भवन का भूमिपूजन भी हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002-03 तक सिंचाई का रकबा मात्र 7.50 लाख हेक्टेयर था। हमारी सरकार में

प्रदेश की सिंचित भूमि का रकबा बढ़कर अब 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। हम एक करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार लाइली बहनों को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर सौगात दे रही है। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री एवं जतारा के वर्तमान विधायक हरिशंकर खटीक ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने किया झिंझरी और बहोरीबंद सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सांदीपनि विद्यालयों की सौगात दे रही हैं। प्रदेश के सांदीपनि विद्यालय सर्वसुविधा युक्त गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का माध्यम बन रहे हैं। इसी का परिणाम है कि विद्यार्थी निजी विद्यालयों से निकलकर शासकीय सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं। डॉ. यादव स्लीमनाबाद कटनी में सांदीपनि विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। झिंझरी का सांदीपनि विद्यालय 38 करोड़ 61 लाख रुपए तथा बहोरीबंद का सांदीपनि विद्यालय 35 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक लागत से बनकर तैयार हुआ। यहां उपलब्ध सुविधाएं गुरुकुल की गरिमा और डिजिटल युग की दक्षता का समन्वय प्रस्तुत करती हैं।

पढ़ाई के लिए बच्चों को दिए जा रहे साधन एवं सुविधाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय शालाओं में बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी साधन और सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्हें नि:शुल्क पुस्तकें और साइकिलें प्रदान की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप और अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में टॉप करता है तो उसे स्कूटी दी जा रही है। राज्य में गुरुपूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के लिए कुलगुरु संबोधन की परंपरा शुरू की गई है।

223 ध्यानाकर्षण, 1756 सवाल और चार स्थगन प्रस्ताव

कल से होगा मानसून सत्र, यूसीसी समेत कई विधेयकों पर रहेगी नजर

हरिभूमि न्यूज ►► गोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा का चार दिवसीय मानसून सत्र सोमवार, 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र के लिए अब तक सीमित संख्या में ही विधेयक विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं।

रविवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) सहित कई विधेयकों के मसौदों को मंजूरी मिलने के बाद उन्हें विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, अब तक सदस्यों की ओर से 223 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 1756 प्रश्न

और चार स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विपक्ष ने कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। सत्र के लिए अब तक 64 शून्यकाल सूचनाएं, नियम-139 के तहत एक सूचना और 18 याचिकाएं भी विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हुई हैं। विधायकों ने कुल 1756 प्रश्न लगाए हैं, जिनमें 900 तारांकित और 856 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। इनमें 1091 प्रश्न ऑनलाइन और 665 प्रश्न ऑफलाइन हैं। इससे पहले कैबिनेट बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान सहित कई विधेयकों के मसौदों पर चर्चा हो चुकी है।

किशोर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

मुराद पूरी करने के नाम पर फर्जी बाबा पर अश्लील हरकत करने के आरोप

हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

मुराद पूरी करने के नाम पर 17 वर्षीय युवक के साथ अश्लील हरकत करने वाले बाबा मुस्तकीम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना आजाद चौक क्षेत्र के ईदगाहभाठा की बताई जा रही है।

प्रार्थी ने थाना आजाद चौक में शिकायत दर्ज कराई कि वह 15 जून 2026 को अपनी मुराद पूरी कराने के लिए मुस्तकीम बेग के पास गया था। कमरे में घुसते ही किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। बाबा मुस्तकीम ने



थाना आजाद चौक में इस मामले में अपराध क्रमांक 151/26 दर्ज किया गया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 127(2) और POCSO एक्ट की धारा 11(2) के तहत मामला दर्ज है।

हरिभूमि न्यूज ►► सरगुजा

जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नाजमी में शुक्रवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हल्की बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे बैठे चार बच्चे इसकी चपेट में आ गए। इस दुर्घटना में दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो सगे भाई झुलस गए। घायल दोनों भाइयों का अस्पताल में उपचार जारी है।

चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर और स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 5 बजे ग्राम नागम में बारिश शुरू हुई थी। इसी समय ये चारों बच्चे एक पेड़ के नीचे

सरगुजा के लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम नागम की घटना

आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चों की मौत, दो झुलसे



बैठकर मोबाइल देख रहे थे। अचानक तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली उसी पेड़ पर आ गिरी।

बिजली गिरने से चारों बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चे बारिश शुरू होने के बाद भी पेड़ के नीचे ही बैठे रहे थे। इसी वजह से यह दुखद हादसा हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

मृतकों और घायलों के नाम

इस दुर्घटना में 12 वर्षीय रंजीत नगेशिया की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रंजीत के पिता का नाम लोहरा नगेशिया है। 12 वर्षीय रोशन नगेशिया (पिता विजय नगेशिया) ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 11 वर्षीय प्रभु राम (पिता भीमसाय) और उसका 13 वर्षीय भाई दिनेश गायल हो गए। प्रभु राम और दिनेश को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने बताया कि दोनों की हालत अब स्थिर है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।

पहचान छिपाकर रह रहा था आरोपी, अन्य आरोपियों की तलाश जारी

बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपी शब्बीर मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार

हरिभूमि न्यूज ►► अंबिकापुर

बहुचर्चित वासेपुर दोहरे हत्याकांड के फरार दोषी शब्बीर (साबिर), आलम को धनबाद पुलिस की वैध अभिरक्षा से छुड़ाकर फरार कराने के मामले में अंबिकापुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है।

मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जबकि पुलिस शब्बीर आलम को वर्षों तक संरक्षण देने वालों की भूमिका भी खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार, धनबाद के बैकमोड़ थाना के उपनिरीक्षक अभय कुमार अपनी टीम के साथ 29 जून को वारंटी शब्बीर उर्फ साबिर आलम की गिरफ्तारी के लिए अंबिकापुर पहुंचे थे। मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह



मोमिनपुरा क्षेत्र में पहचान छिपाकर रह रहा है। पुलिस ने मोमिनपुरा मस्जिद के पास स्कूटी सवार एक युवक को रोककर पूछताछ की, जिसने अपना नाम साबिर आलम बताया। पुलिस जब गिरफ्तारी की वैधानिक प्रक्रिया पूरी कर रही थी, तभी आरोपी ने आसपास मौजूद लोगों को बुला लिया।

बल प्रयोग कर वारंटी को छुड़ाकर

फरार कराने का आरोप

आरोप है कि कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस टीम का विरोध करते हुए बल प्रयोग किया और वारंटी को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाकर फरार करा दिया। भोड़ का फायदा उठाकर अन्य लोग भी मौके से भाग निकले। घटना के बाद कोतवाली थाना में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान धनबाद पुलिस के अधिकारियों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। वीडियो कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से पहचान कराए जाने पर जुनैद खान (30) और उसके पिता मोहम्मद जाहिद खान (59) की घटना में संलिप्तता की पुष्टि हुई। पूछताछ में दोनों ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।

पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक अदीप प्रताप सिंह, सहायक उपनिरीक्षक विवेक पांडेय तथा साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जांच के दौरान अंबिकापुर पुलिस ने बस संचालक वैकुल

बस संचालक पर भी मामला दर्ज

खान के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया है। आरोप है कि उसने वासेपुर हत्याकांड के दोषी शब्बीर आलम को करीब 13 वर्षों तक संरक्षण दिया, जबकि उसे उसकी दोषसिद्धि और फरार होने की जानकारी थी। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि अंबिकापुर में इतने लंबे समय तक शब्बीर आलम को किन-किन लोगों का संरक्षण मिलता रहा।

दोहरे हत्याकांड का आरोपी था शब्बीर आलम

पुलिस के अनुसार, शब्बीर आलम झारखंड के धनबाद स्थित वासेपुर में वर्ष 2001 के वचित दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। आरोप है कि कोयला करोबार में वर्तव्य की लड़ाई के दौरान 18 अक्टूबर 2001 को उसने फहीम खान की मां नजमा ख़ातून और मौसी

शहनाज ख़ातून की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2013 में गिरफ्तारी के बाद वह अदालत में पेशों के दौरान फरार हो गया था। वर्ष 2018 में झारखंड हाईकोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए उसकी संपत्तियों की कुर्की की आदेश दिए थे।

दतिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। अंतिम दिन शादाबुद्दीन और मेहरबान सिंह बघेल ने अपने नाम वापस ले लिए।

इससे पहले केशव यादव भी चुनावी मैदान से हट चुके थे। अब नोटा सहित कुल 22 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो बैलेट यूनिट वाली ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार एक बैलेट यूनिट में नोटा

सहित अधिकतम 16 उम्मीदवारों के नाम ही दर्ज किए जा सकते हैं। ऐसे में शेष उम्मीदवारों के नाम दूसरी बैलेट यूनिट में प्रदर्शित होंगे। मतदान के दौरान मतदाता दोनों यूनिट में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न देख सकेंगे। नामांकन की जांच और वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन ने अंतिम सूची भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। देर रात तक चुनाव चिह्न आवंटन की प्रक्रिया जारी रही। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार को सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए जाएंगे।



मिड या स्मॉल-कैप फंड: 10 साल में किसने दिखाया दम

दोनों का निफ्टी-50 से बेहतर रहा प्रदर्शन

- सिर्फ ज्यादा रिटर्न पर न करें फैसला, पहले जोखिम व वोलैटिलिटी भी समझें
- स्मॉल-कैप ने बेंचमार्क को पीछे छोड़ा, मिड-कैप कम जोखिम संग बेहतर
- विशेषज्ञ बोले, गिरावट से घबराने के बजाय विविधीकृत पोर्टफोलियो अपनाएं
- दोनों फंडों में संपत्ति बनाने की क्षमता, लेकिन क्षमता के अनुसार करें फैसला
- विविधीकरण और लंबी अवधि बेहतर रिटर्न दिलाने की सबसे कारगर रणनीति



रिटर्न के साथ जोखिम भी समझें

अक्सर निवेशक केवल अधिक रिटर्न देखकर निवेश कर देते हैं, जबकि वास्तविक तस्वीर जोखिम के आंकड़ों से सामने आती है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, स्मॉल-कैप फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 20.33 प्रतिशत रहा, जबकि मिड-कैप फंड का यह आंकड़ा 17.88 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि स्मॉल-कैप फंड में कीमतों का उतार-चढ़ाव ज्यादा रहा और इनमें निवेश करने वालों को अधिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इसी तरह जोखिम के मुकाबले मिलने वाले रिटर्न को मापने वाले शार्प रेशियो में भी मिड-कैप फंड आगे रहे। मिड-कैप फंड का शार्प रेशियो 0.79 रहा, जबकि स्मॉल-कैप फंड का 0.69। इसका अर्थ है कि मिड-कैप फंड ने अपेक्षकृत कम जोखिम लेकर बेहतर जोखिम-समयोजित रिटर्न दिया। हालांकि दोनों श्रेणियों का सॉर्टिनो रेशियो समान रहा, जिससे स्पष्ट होता है कि डाउनसाइड जोखिम को ध्यान में रखने पर दोनों का प्रदर्शन लगभग बराबर रहा।

लंबी अवधि के निवेशकों को मिला फायदा : विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 10 वर्षों की सबसे बड़ी सीख यही है कि जिन्होंने बाजार की गिरावट के दौरान घबराकर निवेश नहीं निकाला और लंबे समय तक निवेश बनाए रखा, उन्हें दोनों श्रेणियों में शानदार रिटर्न मिला। बाजार में गिरावट हर चक्र का सामान्य हिस्सा है और इसे निवेश यात्रा का स्वाभाविक चरण माना जाना चाहिए। मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड को केवल अधिक उतार-चढ़ाव के कारण नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। लंबी अवधि में दोनों श्रेणियों ने निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन किया है और निवेशकों के लिए अच्छी संपत्ति बनाने की क्षमता दिखाई है।

दोनों श्रेणियों ने दिया शानदार रिटर्न, लेकिन जोखिम और उतार-चढ़ाव में मिड-कैप

विविधीकरण सबसे बेहतर रणनीति

विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे निवेश को केवल स्मॉल-कैप या केवल मिड-कैप में लगाना समझदारी नहीं है। बेहतर रणनीति यह है कि निवेशकों को पोर्टफोलियो सभी मार्केट के में संतुलित रूप से विभाजित हो। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निवेशक के 10 लाख रुपये पूरी तरह स्मॉल-कैप फंड में लगे हों और बाजार में गिरावट आए, तो पूरे पोर्टफोलियो पर उसका असर पड़ेगा। जबकि यदि पोर्टफोलियो में लगभग 55 प्रतिशत लार्ज-कैप, 23 प्रतिशत मिड-कैप और 22 प्रतिशत स्मॉल-कैप का संतुलित निवेश हो, तो बाजार की गिरावट का प्रभाव काफी कम हो सकता है। यही कारण है कि वित्तीय योजनाकार हमेशा विविधीकरण को सफल निवेश की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मानते हैं।

किस निवेशक के लिए कौन सा फंड ?

यदि आपको निवेश अवधि 7 से 10 वर्ष या उससे अधिक है और आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं, तो स्मॉल-कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में बेहतर वृद्धि की संभावना जोड़ सकते हैं। वहीं यदि आप अछा रिटर्न चाहते हैं लेकिन अपेक्षकृत कम जोखिम लेना पसंद करते हैं, तो मिड-कैप फंड अधिक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं। पहली बार निवेश करने वालों के लिए भी सलाह दी जाती है कि वे सीधे स्मॉल-कैप में बड़ी राशि लगाने के बजाय लार्ज-कैप और मिड-कैप के साथ सीमित हिस्सेदारी स्मॉल-कैप में रखें।

एसआईपी धन सृजन का सबसे प्रभावी तरीका

पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड बताता है कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंडों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। जहां स्मॉल-कैप फंड ने थोड़ा अधिक रिटर्न और बेहतर अफाफा दिया, वहीं मिड-कैप फंड ने कम उतार-चढ़ाव और बेहतर जोखिम-समयोजित प्रदर्शन के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। निवेशकों को केवल अधिक रिटर्न के आकर्षण में निर्णय लेने के बजाय अपने वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। निरन्तर एसआईपी, लंबी अवधि का नजरिया और विविधीकृत निवेश रणनीति ही धन सृजन का सबसे प्रभावी तरीका साबित हो सकती है।

बहुत ज्यादा एसआईपी से नहीं, सही रणनीति से बनेगी दौलत

नया म्यूचुअल फंड जोड़ने से पहले जांचें कि वास्तव में जरूरत है या नहीं

बिगनेस डेस्क

शेयर बाजार में बढ़ती जागरूकता के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी संख्या में निवेशक हर महीने सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए निवेश कर रहे हैं। अक्सर यह धारणा बना जाती है कि जितने अधिक म्यूचुअल फंड होंगे, उतना ही बेहतर रिटर्न मिलेगा और जोखिम कम होगा। लेकिन निवेश विशेषज्ञों का कहना है कि यह सोच हमेशा सही नहीं होती। कई बार जरूरत से ज्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो में एक जैसी कंपनियों का दोहराव बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक विविधीकरण नहीं हो पाता और निवेश का उद्देश्य भी प्रभावित हो सकता है।

फंडों की संख्या नहीं, गुणवत्ता और उद्देश्य है महत्वपूर्ण

विशेषज्ञों के अनुसार, किसी निवेशक के लिए कितनी एसआईपी या कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, इसका कोई तय नियम नहीं है। यह पूरी तरह निवेश राशि, वित्तीय लक्ष्य, निवेश अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। यदि कोई निवेशक हर महीने 10 से 15 हजार रुपये की एसआईपी करता है, तो उसके लिए चार से छह अच्छे म्यूचुअल फंड पर्याप्त हो सकते हैं। वहीं, 40 से 50 हजार रुपये या उससे अधिक की मासिक एसआईपी करने वाले निवेशक आठ से दस फंड तक रख सकते हैं। हालांकि, इन फंडों का चयन अलग-अलग श्रेणियों और अलग-अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एफएमसी) से होना चाहिए, ताकि पोर्टफोलियो में वास्तविक विविधीकरण बना रहे।



ओवर-डाइवर्सिफिकेशन से भी हो सकता है नुकसान

निवेश में विविधीकरण जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा विविधीकरण नुकसानदेह भी हो सकता है। यदि किसी निवेशक के कई फंड एक ही तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो फंडों की संख्या बढ़ने के बावजूद जोखिम कम नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि किसी निवेशक के पास 10 इक्विटी फंड हैं और अधिकांश फंड एवडीएफसी बैक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी कंपनियों में ही निवेश करते हैं, तो अलग-अलग स्कीम होने के बावजूद वास्तविक निवेश लगभग समान रहेगा। ऐसे में पोर्टफोलियो केवल दिखने में बड़ा होगा, लेकिन उसमें नई विविधता नहीं जुड़ेगी।

पोर्टफोलियो ओवरलैप पर रखें नजर

म्यूचुअल फंड चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात पोर्टफोलियो ओवरलैप होती है। इसका अर्थ है कि दो अलग-अलग फंडों में कितनी समान कंपनियां शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दो फंडों के बीच 20 से 30 प्रतिशत तक ओवरलैप है, तो इसे सामान्य माना जा सकता है। लेकिन यदि यह 40 से 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो जाए, तो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक ओवरलैप का मतलब है कि अलग-अलग फंड रखने के बावजूद निवेश लगभग एक जैसी कंपनियों में ही हो रहा है।

हर नया एनएफओ खरीदना जरूरी नहीं

कई निवेशक बाजार में आने वाले हर नए म्यूचुअल फंड ऑफर (एनएफओ) में निवेश कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नया फंड भविष्य में बेहतर रिटर्न देगा। जबकि वास्तविकता यह है कि किसी भी एनएफओ में निवेश करने से पहले उसकी निवेश रणनीति, उद्देश्य और मौजूदा पोर्टफोलियो से उसका अंतर समझना जरूरी है। यदि नया फंड वही काम कर रहा है जो पहले से मौजूद फंड कर रहे हैं, तो उसमें निवेश करना केवल दोहराव बढ़ाएगा।

संतुलित एसेट एलोकेशन है सफलता की कुंजी

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेशकों को बाजार की तेजी या गिरावट देखकर फैसले लेने से बचना चाहिए। इसके बजाय लक्ष्य आधारित निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। इक्विटी पोर्टफोलियो में लगभग 55 प्रतिशत निवेश लार्ज कैप, 25 प्रतिशत मिड कैप और 20 प्रतिशत स्मॉल कैप फंड में रखने से संतुलन बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जरूरत के अनुसार डेट फंड या अन्य परिसंपत्तियों में भी निवेश रखना चाहिए, ताकि बाजार में उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम हो।

- लाइफस्टाइल से समझौता किए बिना हर माह कुछ न कुछ बचत करें
- अच्छी बचत का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना
- आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाया जाना जरूरी
- स्मार्ट मनी मैनेजमेंट से वर्तमान और भविष्य दोनों होंगे खुशहाल
- हर खरीदारी से पहले खुद से सवाल पूछें क्या यह वास्तव में जरूरी है

'फन बजट' बनाएं, बचत भी होगी व खुशी भी

कई लोग बचत करने के उद्देश्य में अपने सभी मनोरंजन संबंधी खर्च बंद कर देते हैं। शुरुआत में यह आसान लगता है, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है और फिर अचानक जरूरत से ज्यादा खर्च करने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए विशेषज्ञ हर महीने एक निश्चित राशि केवल मनोरंजन, घूमने-फिरने, फिल्म देखने या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अलग रखने की सलाह देते हैं। इसे 'फन बजट' कहा जाता है। इससे व्यक्ति बिना किसी अपराधीय के अपनी पसंद की गतिविधियों का आनंद ले सकता है और उसका कुल बजट भी नहीं बिगड़ता।

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बड़ा वित्तीय जाल

वित्तीय दुनिया में एक शब्द काफी लोकप्रिय है। 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन'। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे व्यक्ति अपने खर्च भी बढ़ा देता है। नई नौकरी मिलने पर महंगा मोबाइल खरीद लेना, वेतन बढ़ते ही लक्जरी कार की ईएमआई शुरू कर देना या हर सप्ताह महंगे रेस्टोरेंट जाना इसी प्रवृत्ति के उदाहरण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन बढ़ने पर सबसे पहले बचत और निवेश की राशि बढ़ानी चाहिए। यदि हर वेतन वृद्धि का कम से कम 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा सीधे एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस या अन्य निवेश विकल्पों में लगाया जाए तो कुछ वर्षों में बड़ा निवेश कोष तैयार किया जा सकता है।

रोजमर्रा की छोटी आदतों में करें बड़ा बदलाव

बचत के लिए हमेशा बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटी-छोटी आदतें भी लंबी अवधि में बड़ा असर डालती हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी सामान को खरीदने से पहले ऑनलाइन कीमतों की तुलना करना, कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाना, अनावश्यक गैजेट अपग्रेड से बचना, बिजली और पानी की बचत करना तथा सप्ताह में कुछ दिन बाहर खाने की बजाय घर का भोजन करना जैसी आदतें हर महीने अच्छी रकम बचा सकती हैं। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल उनका ही करें, जितना समय पर चुका सकें। अनावश्यक ईएमआई से बचना और हर महीने आय का कम से कम 20 से 30 प्रतिशत बचत या निवेश के लिए अलग रखना वित्तीय अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।

छोटी-छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड, भविष्य होगा सुरक्षित

मनी मंत्रा

बिगनेस डेस्क

बदली महंगाई, बदलती जीवनशैली और बढ़ते खर्चों के बीच हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चिंता होती है कि आखिर बचत कैसे बढ़ाई जाए। आम धारणा यह है कि पैसे बचाने के लिए अपनी पसंद, शौक और मनोरंजन पर रोक लगानी पड़ती है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी बचत का मतलब कंजूसी करना नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करना है। यदि आय, खर्च और निवेश के बीच संतुलन बनाया जाए तो बिना लाइफस्टाइल से समझौता किए हर महीने अच्छी-खासी बचत की जा सकती है। दरअसल, आज के समय में वित्तीय सुरक्षा केवल अधिक कमाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कमाई का कितना हिस्सा सही तरीके से उपयोग और निवेश किया जा रहा है। यदि व्यक्ति छोटी-छोटी वित्तीय आदतों में बदलाव कर ले तो वह न केवल अपने मासिक खर्चों को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि भविष्य के बड़े वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड को भी आसानी से पूरा कर सकता है।



खर्चों का रिकॉर्ड रखना बचत की पहली सीढ़ी

वित्तीय योजना की शुरुआत हमेशा इस सवाल से होती है कि आपका पैसा आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि वे बहुत अधिक खर्च नहीं करते, लेकिन जब महीनेभर के बैंक स्टेटमेंट या डिजिटल भुगतान का रिकॉर्ड देखा जाता है तो कई ऐसे खर्च सामने आते हैं, जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं होती। बिना इस्तेमाल वाले ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बार-बार ऑनलाइन खाना मंगाना, छोटी-छोटी ऑनलाइन शॉपिंग, महंगी कॉफी या बार-बार कैफे का उपयोग जैसी आदतें महीने के अंत तक हजारों रुपये का अतिरिक्त खर्च करा देती हैं। यदि व्यक्ति अपने सभी खर्चों को मोबाइल ऐप, एक्सेल शीट या डायरी में दर्ज करना शुरू कर दे तो उसे तुरंत समझ आ जाएगा कि बचत की सबसे अधिक संभावना कहाँ है।

जरूरत और वैल्यू में फर्क समझना जरूरी

अक्सर लोग आकर्षक ऑफर या फैशन के प्रभाव में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर खरीदारी से पहले खुद से तीन सवाल पूछें क्या यह वास्तव में जरूरी है? क्या इसका उपयोग लंबे समय तक होगा? और क्या इसे अभी खरीदना आवश्यक है? ऐसी वस्तुओं या अनुभवों पर खर्च करना बेहतर माना जाता है जो लंबे समय तक लाभ दें। उदाहरण के लिए, कोई नई रिक्ल सीखना, स्वास्थ्य पर खर्च करना, परिवार के साथ यात्रा करना या अच्छी किताबें खरीदना ऐसे निवेश हैं जो लंबे समय तक मूल्य देते हैं। इसके विपरीत केवल दिखावे के लिए की गई खरीदारी कुछ समय बाद महत्व खो देती है।

निवेशकों को मिला बड़ा फायदा

5 वर्ष में 101 इक्विटी फंड्स ने दोगुना किया निवेश

- 310 में से हर तीसरे फंड ने दिया 100% से अधिक रिटर्न
- चार स्कीमों ने सिर्फ तीन साल में किया कमाल
- पुराने रिटर्न देखकर निवेश न करें, सेक्टरल फंड्स में लें एंटी

बिगनेस डेस्क

शेयर बाजार में पिछले दो वर्षों के उतार-चढ़ाव के बावजूद लंबी अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले पांच वर्षों में 310 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से 101 फंड्स ने निवेशकों का पैसा दोगुना या उससे अधिक कर दिया। यानी हर तीन में से लगभग एक इक्विटी फंड ने 100 फीसदी से ज्यादा एक्सेल्यूट रिटर्न दिया। इतना ही नहीं, चार म्यूचुअल फंड ऐसे भी रहे जिन्होंने केवल तीन वर्षों में ही निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश का फैसला केवल पुराने रिटर्न के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार और सेक्टर का प्रदर्शन समय के साथ बदलता रहता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और पीएसयू फंड्स रहे सबसे आगे

पांच साल के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे अधिक फायदा सेक्टरल और थीमैटिक फंड्स में निवेश करने वालों को मिला। खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, पावर और मिडकैप से जुड़े फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न दिए।

सबसे आगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रहा, जिसने पांच साल में करीब 188 प्रतिशत का एक्सेल्यूट रिटर्न दिया। यानी एक लाख रुपये का निवेश लगभग 2.88 लाख रुपये हो गया। इसके बाद एसबीआई पीएसयू फंड और एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने करीब 183 प्रतिशत का रिटर्न दिया। वहीं आदित्य बिड़ला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड ने 179 प्रतिशत, डीएसपी इंडिया टाइगर फंड ने 176.51 प्रतिशत और निप्पॉन इंडिया पावर एंड

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने लगभग 174 प्रतिशत का रिटर्न दिया। डायवर्सिफाइड मिडकैप श्रेणी में मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड ने पांच वर्षों में करीब 172 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों को शानदार कमाई कराई।

तीन साल में पैसा दोगुना करने वाले फंड

अगर केवल तीन वर्षों के प्रदर्शन को देखें तो एवडीएफसी डिफेंस फंड सबसे आगे रहा। इस फंड ने करीब 174 प्रतिशत का एक्सेल्यूट रिटर्न दिया। यानी तीन साल पहले लगाए गए एक लाख रुपये बढ़कर लगभग 2.74 लाख रुपये हो गए। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप फंड ने 106 प्रतिशत, व्हाट्स बीएसएसआई फंड ने 101.73 प्रतिशत और एलआईसी एमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 100.24 प्रतिशत का रिटर्न देकर निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया। हालांकि एसबीआई पीएसयू फंड 99.12 प्रतिशत रिटर्न के साथ इस सूची में शामिल होने से मामूली अंतर से चूक गया।

दो साल में कई स्टार फंड्स की रपतार हुई धीमी

- पांच वर्षों में शानदार प्रदर्शन करने वाले कई फंड्स का पिछले दो वर्षों का प्रदर्शन अपेक्षकृत कमजोर रहा है।
- उदाहरण के लिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने पिछले दो वर्षों में केवल 5.28 प्रतिशत रिटर्न दिया। एसबीआई पीएसयू फंड का रिटर्न 0.75 प्रतिशत रहा, जबकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड और इनवेस्टको इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड ने इस अवधि में नकारात्मक रिटर्न दर्ज किया।
- इसी तरह एवडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और डीएसपी इंडिया टाइगर फंड का प्रदर्शन भी पिछले दो वर्षों में काफी धीमा रहा। इससे साफ है कि किसी सेक्टर में तेज रेली के बाद कुछ समय तक ठहराव या गिरावट आना सामान्य बात है।

संसद का मानसून सत्र इस बार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 25 दिनों में 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार विदेशी अंशदान (नारेबाजी/चंदे) विनियमन संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की सजा का बिल जैसे कई नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं, मानसून सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दल नीट-यूजी पेपर लीक, अन्य भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद, ई-20 ईंधन और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या संसद का यह सत्र भी एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे की मेंट चढ़ जाएगा या इस बार देश को सार्थक और सकारात्मक विमर्श देखने को मिलेगा। संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच संवाद, सहमति और संसदीय नियमों का पालन आवश्यक है। संसद की गरिमा तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे तथा विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुने।*इन्हीं मुद्दों की पड़ताल करता आजकल का यह खास अंक...*

मानसून सत्र के लिए आत्म अवलोकन जरूरी



विश्लेषण

डॉ. चन्द्र त्रिखा

वरिष्ठ स्तंभकार

आज ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाहियों का एजेंडा पहले से ही तयशुदा होता है। प्रतिपक्ष को अक्सर लगता है कि चर्चा एवं खबरों में बने रहने का एकमात्र सुलभ उपाय, संसदीय कार्य में बाधा डालना है। सदन का बहिष्कार करना, नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना और शोर का स्वर ऊंचा ले जाना ही प्रासंगिक बने रहने का एकमात्र तरीका मान लिया गया है। इस सबके लिए यदि सदन से बाहर भी आना पड़े तो वहां भी मीडिया कवरेज भरपूर मिल ही जाती है। इसी परिवर्तित राजनीतिक पृष्ठभूमि में, जब भी मानसून अपने साथ ग्रीष्म ऋतु की तपन से राहत की फुहारें लेकर आता है, सम्पूर्ण राष्ट्र की निगाहें दिल्ली के सत्ता-गलियारों और विशेषकर संसद के मानसून सत्र पर टिक जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र का हृदय हमारी संसद है, जहां देश की दिशा और दशा तय होती है। हर बार की तरह इस बार भी एक यक्ष प्रश्न पूरे देश के मानस पटल पर गूंज रहा है कि क्या संसद का यह सत्र भी एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या इस बार देश को सार्थक और सकारात्मक विमर्श देखने को मिलेगा।

ज्वलंत मुद्दों की लंबी शृंखला

यह प्रश्न केवल एक राजनीतिक जिज्ञासा मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के कोटि-कोटि करदाताओं की उस गहरी चिंता का प्रकटीकरण है जो वे अपने द्वारा चुने गए जन-प्रतिनिधियों से रखते हैं। विगत कुछ वर्षों के संसदीय इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटें तो एक अत्यंत निराशाजनक चित्र उभर कर सामने आता है। संसद के सत्र, चाहे वह शीतकालीन हो, बजट हो या मानसून, प्रायः शोरगुल, अध्यक्ष के आसन के समीप आकर की जाने वाली नारेबाजी और अंततः अनिश्चित काल के लिए कार्यवाही स्थगित होने के गवाह बने हैं।

विपक्ष के पास सदैव सरकार को घेरने के लिए ज्वलंत मुद्दों की एक लंबी शृंखला होती है। चाहे वह बढ़ती महंगाई का विषय हो, बेरोजगारी की चुभती समस्या हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील प्रसंग हों।



राष्ट्रहित को मिले सर्वोच्च प्राथमिकता

जब सरकारें विपक्ष की चिंताओं को उद्भारतापूर्वक सुनती हैं और विपक्ष नेताओं के साथ नेपथ्य में अनौपचारिक संवाद स्थापित करती हैं, तो प्रायः बड़े से बड़े गतिरोध भी बर्फ की भांति पिघल जाते हैं। इन गंभीर परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, यह समय की सबसे बड़ी मांग है कि हमारे जन-प्रतिनिधि यह आत्मसात करें कि संसद कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, अपितु राष्ट्रीय विमर्श का सर्वोच्च और पवित्र मंदिर है। इस मानसून सत्र से सम्पूर्ण राष्ट्र को यह अपेक्षा है कि विपक्ष अपना विरोध अवश्य दर्ज करे, परंतु तर्कों और प्रामाणिक तथ्यों की कसौटी पर। सरकार को भी विपक्ष के तीखे प्रश्नों का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए और बिना किसी राजनीतिक दंभ

के उनका उचित व पारदर्शी उत्तर प्रदान करना चाहिए। अंततः, यह प्रश्न अपनी जगह अंडित है कि क्या यह मानसून सत्र एक बार फिर विपक्ष के प्रदर्शन की वेदी पर स्वाहा हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर पूर्णतः इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता और विपक्ष, दोनों ही पक्ष अपने राजनीतिक अहंकार और दलगत स्वार्थों को किनारे रखकर राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं या नहीं। यदि दोनों ही पक्ष यह स्मरण रखें कि वे उस मूल्य इमारत में इसलिए आसीन हैं क्योंकि देश की सेवा सौ करोड़ से अधिक जनता ने उन पर अपना अटूट विश्वास जताया है तो निश्चित ही यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने के बजाय भारत की प्रगति का नया अध्याय लिखेगा।

सशक्त और मुखर हो विपक्ष

विपक्ष का निरंतर यह तर्क रहता है कि सरकार सदन में उनके स्वर को दबाने का प्रयास कर रही है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से परायोजन कर रही है और बिना किसी सार्थक बहस के कानूनों को पारित करवा रही है। दूसरी ओर, सत्ता पक्ष का यह मुखर आरोप होता है कि विपक्ष जानबूझकर राष्ट्र के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है और वह केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। इस निरंतर चलने वाले आरोप-प्रत्यारोप के मध्य हमें यह कदापि विस्मृत नहीं करना चाहिए कि लोकतंत्र बिना एक सशक्त और मुखर विपक्ष के नितांत अधूरा है। प्रदर्शन करना, अपनी असहमति प्रकट करना और विरोध दर्ज कराना विपक्ष का नैसर्गिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु विरोध और व्यवधान के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु महत्वपूर्ण लक्ष्मण रेखा होती है।

बहस के लिए तत्पर रहे सरकार

जब लोकतांत्रिक विरोध, अनियंत्रित व्यवधान में परिवर्तित हो जाता है तो विपक्ष अनजाने में उसी सर्वोच्च मंच को नष्ट कर देता है जो उसे सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए प्रदान किया गया है। संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे बहुमूल्य प्रहर होते हैं, जब जन-प्रतिनिधि सीमा भ्रंशियों से जवाब तलब कर सकते हैं। यदि सदन हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो विपक्ष सरकार का उत्तरदायित्व तय करने का अपना सबसे अचूक अस्त्र स्वयं ही त्याग देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन आज भी प्रासंगिक है कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, किंतु राष्ट्र सर्वसम्मति से चलता है। सत्ता पक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर और सम्मान प्राप्त हो। यदि विपक्ष किसी विशेष और ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श की मांग कर रहा है, तो सरकार को संसदीय नियमों की परिधि में उस पर खुली बहस के लिए तत्पर रहना चाहिए।

सदन में लगातार विरोध से विपक्ष की गिरती साख



व्यवधान

चरणजीत चरण

स्वतंत्र पत्रकार

दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में वहां की संसद को सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र में संसद का स्थान किसी भी धर्मस्थल से ऊपर माना गया है, क्योंकि संसद ही वह स्थान है जहां आम जनमानस की समस्याओं के निवारण के कानून बनते हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को ध्यान में रखकर किसी भी विषय पर चर्चा-परिचर्चा होती है। उसके बाद जनप्रतिनिधियों के वोट के आधार पर कोई विधेयक कानून का रूप लेता है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है यह प्रक्रिया अत्यंत सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ रही है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को विश्व की सबसे सुदृढ़ और पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। आज, जब पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र को एक मानक मानकर अपने देश में लोकतांत्रिक सुधार कर रही है। तब हमारे देश के लोकतंत्र में कुछ अनावश्यक रुढ़ियां जगह बना रही हैं। संसद का काम होता है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से देश की जनता की नब्ज टटोलना, फिर उन समस्याओं के निवारण के लिए कानून बनाना। कानून बनाने की इस प्रक्रिया को एक सकारात्मक और आलोचनात्मक बहस से गुजरना आवश्यक है। अगर कोई कानून संसद में पर्याप्त बहस के बिना कानून का रूप ले लेगा तो वह कुछ लोगों को तो संतुष्ट कर सकता है, लेकिन देश के विकास की गति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका कई मायनों में सत्ता पक्ष से भी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि सत्तापक्ष में बैठे लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका नहीं निभाता तो सरकार निरंकुश हो जाती है। पिछले कई वर्षों से यह देखा गया है कि विपक्ष जो विरोध करता है, वह रचनात्मक न होकर नकारात्मक होता है। विरोध की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तिथ्यों और तर्कों के आधार पर विरोध स्वीकार्य होता है। उसे सुना भी जाता है और उससे कुछ सकारात्मक व रचनात्मक निर्णय लेने में आसानी होती है। वर्तमान समय में होने वाला विपक्ष का विरोध, विरोध कम और व्यवधान अधिक होता है। विपक्ष का सजग होना और मुखर होना दोनों आवश्यक है। विपक्ष का काम है आईना बनकर सरकार के सम्बंध खड़े रहना। सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसे जनता के बीच तक ले जाना। लेकिन यही विरोध जब अपनी मर्यादा लांघकर अनियंत्रित होने लगे, अमरुता और हठधर्मिता पर उतर आए तो इसका मतलब होता है कि विपक्ष अपने कर्तव्यों के विरुद्धन में असफल है। संसद शुरू होने के पहले दिन से ही बिना किसी उचित कारण के तख्तिरों और बैनर लेकर कुर्सियों पर खड़े हो जाना, लगातार नारेबाजी करना ,अध्यक्ष के आसन के सामने खड़े होकर शोर मचाना और इसी शोर शराबे के कारण संसद को अस्थिरता काल के लिए स्थगित करा देना न तो सरकार के पक्ष में होता है न ही विपक्ष के। इससे हर रोज जनता के टैक्स का लाखों रुपया बर्बाद होता है और बहुत से जनहित के विधेयक या तो लम्बे समय के लिए लटके जाते हैं या सरकार उन्हें खीर किसी चर्चा के पात्र करा देती है जिसके कारण उन विधेयक में रचनात्मक सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार देश की जनता को मिलता है एक अध्यक्षता, अपरिपक्व कानून। इनके दूरगामी परिणाम देश की जनता को झेलने पड़ते हैं। सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों को लेकर जनता में जाकर विरोध करना विपक्ष का कर्तव्य है। लेकिन देश की जनता यह भी पूछती है कि जब कानून बन रहा था उस वक्त विपक्ष कहाँ था क्या संसद के गलियारे में खड़े होकर नारे लगा रहा था या कानून पर कोई रचनात्मक चर्चा कर रहा था। संसद का गंच सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए और सरकार से जवाब मांगने के लिए है। शून्यकाल और प्रश्नकाल के द्वारा जनप्रतिनिधि सीधे सरकार के नुमाइंदों से जवाब मांग सकते हैं। जनता की मूलभूत समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, राशन होती हैं। इन समस्याओं पर सरकार के निरंतर प्रश्न करते रहना विपक्ष का मूल एजेंडा होना चाहिए। साथ ही राजमार्ग का निर्माण, रेल, नदी जल बंटवारा, राज्य सीमा विवाद, साम्यवादीक सौहार्द, विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध, ये सभी किसी भी देश के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो विपक्ष के सहयोग के बिना नहीं हो सकते हैं। इन विषयों पर चर्चा के समय अगर विपक्ष हंगामा करता है तो फिर जनता का विपक्ष के प्रति मोहभंग होता है। जनता भली-भांति समझती है कि विरोध तथ्यों और तर्कों के आधार पर है या सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए है। निष्कर्ष यही है कि विपक्ष को अपनी कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। अगर विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो, न कि सिर्फ हंगामे के लिए। विरोध के लिए पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को चाहिए कि वह अपने तर्कों को और मजबूत करे, संसद में रचनात्मक बहस के द्वारा सरकार की नीतियों का विरोध करे यही जनता के हित में है। इसलिए आवश्यक है कि संसद की कार्यवाही निर्वाह रूप से चलती रहे। यही देश हित में है।

विपक्ष को अपनी खोई हुई गरिमा फिर से प्राप्त करनी है तो उसे अपने विरोध का तरीका भी बदलना होगा। विपक्ष को समझना होगा कि विरोध रचनात्मक और तर्कसंगत हो न कि सिर्फ हंगामे के लिए। पूरी संसदीय प्रक्रिया को ठप कर देना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

पक्ष व विपक्ष में बने व्यावहारिक संतुलन



मानसून सत्र

डॉ. विजेंद्र कुमार

वरिष्ठ स्तंभकार

भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में जब भी नए सत्र की शुरुआत होती है, तो पूरे देश की निगाहें स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाती हैं। वर्तमान परिदृश्य में, संसद का यह सत्र केवल दैनिक कामकाज का गवाह बनने वाला नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य की आधारशिला रखने वाले दो ऐतिहासिक विषयों-पारसीमन विधेयक और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर निर्णायक चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है। आज हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या सरकार इस मानसून सत्र में इन दोनों बड़े बदलावों को सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी।

देश के चुनावी भूगोल को बदल देने वाले इन विधेयकों का भविष्य अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि सदन के भीतर सरकार की रणनीति और विपक्ष की असहमति के बीच कैसा व्यावहारिक संतुलन स्थापित होता है। यदि हम पारसीमन विधेयक को समझें, तो यह केवल भौगोलिक सीमाओं का बदलाव नहीं है, बल्कि बदलती जनसंख्या के आधार पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को अद्यतन करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने का अभूतपूर्व प्रस्ताव रखा गया है। इसका सबसे संवेदनशील पहलू जनसंख्या से जुड़ा है, जिससे विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में यह आश्ंका उत्पन्न हो गई है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण संसद में उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। हालांकि, गृह मंत्री ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि नए पारसीमन से किसी भी दक्षिणी राज्य को नुकसान नहीं होगा, बल्कि उनका आनुपातिक हिस्सा बरकरार रहेगा और कुल सीटों में भी वृद्धि होगी। इसके बावजूद, क्षेत्रीय दल इसे राज्यों के अधिकारों से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे यह उठर और दक्षिण भारत के बीच एक नई राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सत्र में इस विधेयक को पारित करा सकेगी। इसे पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई विशेष

बहुमत की आवश्यकता होगी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्याबल है, लेकिन राज्यसभा के आंकड़े और सहयोगी दलों की अपेक्षाओं को साधना एक कठिन चुनौती है। हालांकि, सत्तारूढ़ दल की कार्यप्रणाली में चौकाने वाले निर्णयों का एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए राजनीति के इस खेल में किसी भी संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसी सरगमी के बीच, इस सत्र का दूसरा बड़ा मुद्दा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की दूरगामी संकल्पना है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय

गणित ही एकमात्र बाधा नहीं है, बल्कि संवैधानिक संशोधनों की वह जटिल प्रक्रिया भी है जिसमें राज्यों की प्रत्यक्ष भागीदारी अनिवार्य होती है। विशेष रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना को साकार करने के लिए संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में व्यापक संशोधन की आवश्यकता होगी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में, जहां कई प्रमुख राज्यों में विपक्षी दलों की मजबूत सरकारें आसीन हैं, वहां से इस विधेयक के पक्ष में समर्थन जुटाना केंद्र सरकार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा। निष्कर्ष के तौर पर



यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। पारसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है।

समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की ठोस वकालत की है। इसका तर्क है कि इससे हजारों करोड़ रुपये की भारी बचत होगी और बार-बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वहीं, इसके विपरीत विपक्ष और कई विश्लेषकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों की आंधी में स्थानीय समस्याएं पूरी तरह दब जाएंगी। उन्हें डर है कि मतदाता एक ही पार्टी के पक्ष में एकतरफा मतदान कर सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों का स्वतंत्र अस्तित्व और देश का संघीय ढांचा कमजोर हो सकता है। इन दोनों महत्वाकांक्षी विधेयकों की राह में केवल संसदीय

कहा जा सकता है कि यह मानसून सत्र भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक और निर्णायक पड़ाव बनने जा रहा है। पारसीमन और समकालिक चुनाव, दोनों ही ऐसे परिवर्तनकारी कदम हैं, जिनके लिए केवल साधारण बहुमत नहीं, बल्कि एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अपने राजनीतिक कौशल से इस जटिल चक्रव्यूह को भेद पाती है या विपक्ष एकजुट होकर इन विधेयकों को फिलहाल रोकने में सफल रहता है। पूरे देश को प्रतीक्षा है कि पक्ष और विपक्ष राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इन गंभीर विषयों पर परिपक्व विमर्श प्रस्तुत करेंगे।

सांसदों के दैनिक भत्तों में करें कटौती



आर्थिकी

डॉ. पवन कुमार शर्मा

स्वतंत्र पत्रकार

भारतीय संसद देश की संप्रभुता, लोकतांत्रिक मूल्यों और जन-आकांक्षाओं का प्रतीक है। पिछले कुछ दशकों में संसद के भीतर बढ़ते गतिरोध और घटती उत्पादकता ने करदाताओं की धनराशि के सदुपयोग और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। भारतीय संसद को चलाने में भारी जन-धन का व्यय होता है। हालिया बजटीय आकलनों और संसदीय आंकड़ों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों लोक सभा और राज्य सभा को सुचारु रूप से चलाने का अनुमानित खर्च लगभग 2.5 लाख प्रति मिनट यानी 1.5 करोड़ प्रति घंटा आता है। इस हिसाब से एक दिन की सामान्य कार्यवाही का खर्च करीब 9 करोड़ तक पहुँच जाता है। इस खर्च में सांसदों के वेतन-भत्ते, संसद भवन का रखरखाव, सुरक्षा, सचिवालय का स्टॉफ, मुद्रण और सत्र के दौरान होने वाले अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं। जब सदन में व्यवधान के कारण कार्यवाही स्थगित होती है तो यह पूरा पैसा बिना किसी विधायी परिणाम के व्यर्थ हो जाता है।

क्या संसद न चलने पर सांसदों का भत्ता काटा जाना चाहिए? यह मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में ज्वलंत बहस बन चुका है। इसके दो मुख्य पहलू हैं। सकारात्मक पक्ष (भत्ता कटौत जाने के) यह है कि कॉर्पोरेट या किसी भी संगठित क्षेत्र में 'नो वर्क, नो पे' का नियम लागू होता है। जनता का तर्क है कि जब करदाताओं की गाढ़ी कमाई से सांसदों को प्रतिदिन 'सदन उपस्थिति भत्ता' और अन्य सुविधाएं मिलती हैं तो बिना काम किए इसे प्राप्त करना नैतिक रूप से गलत है। व्यवधान के दिनों का भत्ता काटने से सांसदों में जवाबदेही बढ़ेगी। नकारात्मक पक्ष यह है कि संसदीय लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना भी एक वैध उपकरण माना जाता है। कई बार विपक्ष को अपनी बात रखने का समय नहीं मिलता, जिससे मजबूरन वे सदन के बीचों-बीच वेल में आकर प्रदर्शन करते हैं। सांसद का काम केवल संसद में

बैठना नहीं होता, वे समितियों में काम करते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं का निवारण भी करते हैं। जब बजट या महत्वपूर्ण कानून बिना किसी बहस के 'गिलोटीन' (बिना चर्चा के पास करना) के जरिए पारित हो जाते हैं तो यह न केवल वित्तीय नुकसान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हनन है। 2024 के आम चुनावों के बाद गठित 18वीं लोक सभा में विपक्ष ने पहले की तुलना में अपनी आवाज मजबूत की है। इसके प्रारंभिक और बजट सत्रों (2024) में लोक सभा और राज्य सभा क्रमशः 22 और 20 दिनों तक चलीं।



संसद की उत्पादकता सुधारने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए कुछ ठोस सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि कोई सांसद या दल जानबूझकर बिना किसी ठोस विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए।

हालांकि 2026 के बजट सत्र में विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच तीखी नॉकडाऊ के कारण लगभग 20-25 घंटे व्यवधान की भेंट चढ़ गए, जिससे टैक्सपेयर मनी का नुकसान हुआ। नीट परीक्षा विवाद, विभिन्न केंद्रीय मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तेवर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और सेना के पूर्व जनरलों की किताबों के अंशों पर सदन में चर्चा को लेकर हुए विवादों ने सदन को बार-बार बाधित किया। भारतीय संसद के इतिहास को देखें तो पहली तीन लोक सभाओं (1952-1967) में वार्षिक बैठकों का औसत 120-130 दिन होता था, जो अब घटकर औसतन 60-70 दिन रह गया है। संसद में होने वाले व्यवधान महज तात्कालिक

कोई सांसद या दल जानबूझकर बिना किसी ठोस विधायी कारण के सदन को लगातार बाधित करता है तो आनुपातिक रूप से उनके दैनिक भत्तों में कटौती का कानून बनना चाहिए। हर महत्वपूर्ण विधेयक को संसद में पारित होने से पहले अनिवार्य रूप से विभाग-संबंधित स्थायी समितियों के पास भेजा जाना चाहिए ताकि उन पर विशेषज्ञता के साथ चर्चा हो सके। संसद की गरिमा, सर्वोच्चता और उत्पादकता तभी बहाल हो सकती है, जब सत्ता पक्ष विपक्ष को पर्याप्त सम्मान और समय दे और विपक्ष भी केवल विरोध के लिए विरोध करने के बजाय रचनात्मक आलोचना का मार्ग चुने।

संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक

एजेसी ►► नई दिल्ली

20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश कर सकती है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वे उठाना चाहते हैं।

खबर संक्षेप

सपा नेता आजम की 2 साल की सजा बरकरार

आगरा। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान चुनावी सभा में अधिकारी को तनखेया बताने के मामले में



सपा नेता आजम को राहत नहीं मिली। निचली अदालत से मिली 2वर्ष की सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने फैसले को सही ठहराते हुए सजा जुर्माना बरकरार रखा है।

चेंगापल्ली के पास कार टैकर गिड़े, 3 की मौत

तिरुप्पुर। तमिलनाडु में सेलम-कोयंबटूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेंगापल्ली के पास शनिवार को



एक कार के सड़क किनारे खड़े गैस टैकर से टकरा जाने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मृतकों की पहचान विजय , उनकी पत्नी थेनमोड़ी और कुमार के रूप में हुई है। 8 लोगों का समूह तिरुत्तनी से ऊटी जा रहा था, तभी हादसा हुआ।

कोलकाता में रिहायशी इमारत में विस्फोट

कोलकाता। कोलकाता के पूर्वी बाहरी इलाके में में हुए विस्फोट में एक इमारत आंशिक रूप से



क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस को संदेह है कि यह घटना देसी बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों के कारण हुई। दक्षिण नारायणपुर इलाके में हुए इस विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मुख्य संदिग्ध मोहम्मद शमीम फरार है।

शिंदे गुट में बागी सांसदों के विलय को मंजूरी

नई दिल्ली। लोकसभा में टीएमसी और शिवसेना (उद्धव गुट) के बागी सांसदों की स्थिति को लेकर बड़ा



फैसला आ चुका है। इस कड़ी में महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका लगा है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में उद्धव गुट के छह सांसदों के विलय को लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है। यूबीटी के सांसद अब शिंदे गुट के सांसद हो गए हैं।

हत्या मामले में 4 को आजीवन कारावास

नोएडा। उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने दनकोर थाना क्षेत्र के बिलासपुर



गांव में वर्ष 2016 में पुरानी रंजिश की वजह से एक युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया की अदालत ने 60-60 हजार का जुर्माना लगाया।

बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की रूपरेखा पेश करेगी विपक्ष दल अपने-अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे

►► 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी दलों से संसद के सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी।

पीएम, सीएम व मंत्रियों को हटाने वाले बिल को मंजूरी देने की उम्मीद



130वें संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले उसे मंजूरी देने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि समिति ने सुझाव दिया है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराधों के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें उनके पदों से हमेशा के लिए हटाने के बजाय स्पेंड कर दिया जाए।

जेपीसी के मंजूरी लेने के संकेत

विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए बनाई रणनीति

सांसद सुधाकर सिंह ने रविवार को कहा कि 'इंडिया' गठबंधन संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा मामले और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरेगा। साथ ही, वे विपक्षी दलों में विभाजन करके दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की भाजपा की कथित कोशिशों का भी विरोध करेंगे।

पुलिस ने वांगचुक को प्रदर्शनस्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया

सुबह 7.40 बजे पुलिस धरनास्थल पर पहुंची



एजेसी ►► नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को प्रदर्शनस्थल से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया। वांगचुक को अनिश्चितकालीन अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इसे लेकर कहा है कि उसने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी सरकार के मूल सिद्धांत 'असत्य और हिंसा' हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से उस समय हटाया जाना गलत है, जब वह अहिंसक भूख हड़ताल पर बैठे थे।

►► वांगचुक को अनिश्चितकालीन अनशन के 21वें दिन तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। विपक्ष ने केंद्र पर हमला किया

वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के राहुल गांधी



संसद ने किसी को नहीं बख्शा: खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्होंने गंगा को बचाने के लिए 111 दिनों तक आमरण अनशन किया था, से लेकर हरियाणा की ओलंपिक पहलवानों, 750 किसान आंदोलनकारियों, दलितों, आदिवासियों और पेपर लीक मामलों से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों तक, किसी को भी सरकार ने नहीं बख्शा।

अहंकार ठीक नहीं, ये सरकार की हार

वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर पूर्व सीएम केजरीवाल ने केंद्र पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। उन्हें जबरन उठाने की बजाय, मोदी सरकार को सोनम से बात करनी चाहिए थी। आंदोलन को कुचलने की बजाय शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारे।

पूरी दुनिया में गहरी चिंता छाई: अखिलेश



अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- 'सोनम वांगचुक को 'बल-प्रयोग' करके, जबरदस्ती उनके आमरण अनशन स्थल से उठाकर ले जाना अत्यंत निंदनीय समाचार है। आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर में पूरे देश और संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। सारी दुनिया और देशभर में वांगचुक को लेकर गहरी चिंता है।

मंच पर फूट-फूटकर रोए दीपके, संसद चलो अभियान होगा



सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हटाए जाने के बाद प्रदर्शन के दौरान फूट-फूटकर रो पड़े। दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। आंदोलन खत्म नहीं होगा। संसद तक मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग करेंगे।

दीपके पर स्याही फेंकी, महिला हिरासत में

जंतर-मंतर पर सीजेपी के संस्थापक दीपके पर स्याही फेंकी का मामला सामने आया है। एक महिला ने अभिजीत पर स्याही फेंक दी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। इस पर दीपके ने कहा कि उन्हें नीला रंग पसंद है।

बार काउंसिल की सख्त चेतावनी

कोर्टरूम में रील बनाई तो खैर नहीं, अब शपथपत्र देना होगा

एजेसी ►► नई दिल्ली



सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे

कानूनी शिक्षा से जुड़े छोटे वीडियो, रील, पॉडकास्ट क्लिप या पोस्ट साझा करने की इजाजत रहेगी, बशर्ते वे भ्रामक दावे करने वाले न हों। बीसीआई ने सोशल मीडिया एथिक्स नोडल अधिकारी नियुक्त करने से मना किया गया है।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 'सौश्रुतम 2026' का समापन

आयुर्वेदाचार्यों की पहचान कुशल सर्जन के रूप में हो रही

एजेसी ►► नई दिल्ली

आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली में आयोजित 3 दिनी अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 'सौश्रुतम 2026' का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। 15 से 17 जुलाई तक आयोजित इस संगोष्ठी में भारत और विदेशों के प्रमुख विशेषज्ञों ने आचार्य सुश्रुत की शल्य चिकित्सा विरासत, आयुर्वेदिक सर्जरी में नवाचार और आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय पर विचार-विमर्श किया। खास बात यह रही कि अतिथियों ने कहा कि अब आयुर्वेद आचार्यों की पहचान सर्जन की हो रही।

खास बातें

- थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, ग्रीस और भारत के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों तथा सर्जनों ने भाग लिया
- एआईआईए, आईएमएस-बीएचयू, आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, जामनगर की भागेदारी



वैज्ञानिक संवाद और नवाचार को मिला बड़ा मंच

निदेशक प्रो. (वैद्य) पीके प्रजापति ने कहा कि इसका का उद्देश्य वैज्ञानिक संवाद को बढ़ावा देना, साक्ष्य-आधारित शल्य चिकित्सा पद्धतियों का आदान-प्रदान करना, उभरती तकनीकों को प्रदर्शित करना और आचार्य सुश्रुत की शल्य चिकित्सा विरासत को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाना था।

समापन सत्र में शामिल हुए कई गणमान्य

समापन सत्र में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग की अध्यक्ष वैद्य मनीषा कोठेकर और दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एनसीआईएसएम के 'बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन' के अध्यक्ष डॉ. सुश्रुत कर्नोजिया और पद्मश्री प्रो. मनोरंजन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू का नवीनीकरण

समापन समारोह के दौरान एआईआईई और आईआईटी दिल्ली के बीच सहयोगी अनुसंधान एवं नवाचार के लिए एमओयू को 5 वर्षों के लिए नवीकृत किया। 'आयुषवल्ली' के तीसरे संस्करण, 'नेत्र रोग : सामान्य जानकारी और निवारण' पुस्तक तथा 'सौश्रुतम 2026' की स्मारिका का भी विमोचन किया।

धारा 163 लागू रहेगी

संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिले, विशेषकर संसद भवन और इंडिया गेट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहती है। पुलिस इस दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएफ) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू रखती है, जिसके तहत चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने, अनधिकृत रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है।

डीजीपी की अध्यक्षता में आपात बैठक

सोनम वांगचुक को हटाए जाने के बाद जंतर-मंतर पर बढ़े तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस के नवनियुक्त कमिश्नर अनुराग कुमार ने शनिवार दोपहर 1 बजे पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय आपातकालीन रणनीति बैठक बुलाई। बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और बिना अनुमति संसद मार्च की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने की रणनीति तैयार की गई।

अभिषेक की बढ़ी मुश्किलें

अमताला में पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर, ध्वस्त

एजेसी ►► कोलकाता

दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन ने शनिवार को अमताला स्थित तुणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बेनर्जी के कार्यालय को ध्वस्त कर दिया है।



विभागीय जांच में पाया गया था इस कार्यालय का निर्माण स्वीकृत भवन योजना के बिना और लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था। मामले में एक अधिकारी ने बताया कि भारी सुरक्षा के बीच जेसीबी की मदद से कार्यालय को ध्वस्त किया गया। इस दौरान पुलिस और केंद्रीय बलों को घटनास्थल के आसपास तैनात किया गया था और एहतियात के तौर पर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी भी मौके पर मौजूद थे।

शिकायतों के बाद की गई कार्रवाई

अधिकारी ने बताया कि कार्यालय के निर्माण में सभी नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित व्यक्तियों को 15 जुलाई को नोटिस जारी कर शिकायतों के आधार पर शुरू की गई वैधानिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए उपस्थित होने को कहा गया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी

इस कार्रवाई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जश्न का माहौल छा गया, जिन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। अभिषेक डायमंड हार्बर निर्वाचन क्षेत्र से टीएमसी के लोकसभा सांसद हैं। अमताला इसी निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। यहां से भाजपा विधायक अनंश्वर नस्कर ने आरोप लगाया कि अभिषेक के पार्टी कार्यालय का निर्माण भवन नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया था और उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत किया। नस्कर ने कहा कि यह ढांचा अवैध रूप से बनाया गया था। प्रशासन ने आखिरकार कानून के अनुसार कार्रवाई की है।

2047 के लक्ष्य को रफ्तार देने के लिए नीति आयोग ने जारी की रैकिंग

निवेश अनुकूलता सूचकांक

एजेसी ►► नई दिल्ली

नीति आयोग ने शनिवार को नई दिल्ली में देश का प्रतिष्ठित 'निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026' जारी की। इस में गुजरात भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पछाड़कर निवेश आकर्षित करने के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। सीईओ निधि छिब्र ने कहा कि यह सूचकांक केवल एक रैंकिंग नहीं है, बल्कि राज्यों के लिए



एक व्यावहारिक सुधार उपकरण है। इससे राज्यों को अपनी कमियों को पहचानने और एक-दूसरे के मदद के साथ ही प्रतियोगिता करने का मौका मिलेगा।

8 प्रमुख स्तंभ

अवसरचरना (इन्फ्रास्ट्रक्चर), कारोबारी माहौल, संसाधन, सरकारी नीति, नियामक सुगमता, संस्थागत वातावरण, वित्तीय स्थिति, पर्यावरणीय लचीलापन।

15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मानसूनी गतिविधियां बढ़ेंगी बिजली गिरने का भी खतरा

एजेसी ►► नई दिल्ली



भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ ही भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की

हिमाचल में 'ऑरेंज अलर्ट'

हिमाचल प्रदेश के शिमला में 19 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के साथ इस इलाके में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में व्यापक बारिश होगी। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। जम्मू-कश्मीर बाढ़, भूस्खलन और जलभराव की आशंका है।



‘द इंडिया स्टोरी’ 24 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

मुंबई। काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म ‘द इंडिया स्टोरी’ काफी समय से चर्चा में हैं। पिछले महीने निर्माताओं ने इसका टीजर और पोस्टर जारी किए थे, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाले विषय को जनता के सामने लाने का संकेत दिया था। जी स्टूडियोज और एमआईजी

प्रोडक्शन एंड स्टूडियोज द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन चेड्डन डीके ने किया है। फिल्म में काजल वकील के किरदार में हैं, जबकि श्रेयस एक लाचार पिता के रूप में बेटी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। फिल्म 24 जुलाई को हिंदी, तेलुगु और तमिल में दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

लाइफ Style

अगस्त 2024 में प्रकृति घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म किया। काम के मोर्चे पर उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्च में उनका शो ‘शहजादी है तू दिल की’ कम टीआरपी के कारण बंद हो गया था।

प्रकृति

दो साल में ही टूटा रिश्ता

एंजेसी ► मुंबई

‘सैयाराब’ सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री प्रकृति नौरियाल अपनी 2 साल पुरानी शादी को खत्म करने जा रही हैं। यह जोड़ा, जिसने 6 महीने के छोटे से रोमांस के बाद साल 2024 के वेलेंटाइन डे पर शादी की थी, अब अलग होने का फैसला कर चुका है। उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है और अब उनकी अगली कोर्ट की तारीख नवंबर में तय है।

प्रकृति ने अगस्त 2024 में छोड़ा था घर : अगस्त 2024 में प्रकृति घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म किया। काम के मोर्चे पर उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मार्च में उनका शो ‘शहजादी है तू दिल की’ कम टीआरपी के कारण बंद हो गया था।

उन्होंने बताया था कि उन्हें महसूस हुआ कि मूल कहानी से बंधे रहना उन्हें सीमित कर रहा था। शो का अचानक बंद होना उन्हें बहुत दुखी कर गया था। उन्होंने कहा था, ‘यह वाकई निराशाजनक और दिल तोड़ने वाला था।’



हॉलीवुड मसाला



द ओडिसी... का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार

लॉस एंजिल्स। क्रिस्टोफर नोलैन की नई फिल्म ‘द ओडिसी’ 17 जुलाई को भारत के सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और इसकी एडवांस बुकिंग में भी जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। फिल्म के टिकट 150 रुपये से शुरू होकर प्रीमियम सीटों के लिए 3,400 रुपये तक जा रहे हैं। दर्शकों में फिल्म को लेकर कितनी दीवानगी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। होमर की क्लासिक कहानी से प्रेरित इस महाकाव्य एडवेंचर में मैट डैमन मुख्य भूमिका में हैं। जानकारों का मानना है कि यह फिल्म क्रिस्टोफर की पिछली ब्लॉकबस्टर ‘ओपेनहाइमर’ से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होगी।



गोलम की कास्टिंग पर एंडी सरकिज का दो टूक जवाब

लॉस एंजिल्स। ‘द हंट फॉर गोलम’ में मुख्य भूमिका निभा रहे एंडी सरकिज ने फिल्म की पूरी तरह से श्वेत कास्ट को लेकर हो रहे विरोध पर अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि कास्टिंग टॉल्कन के मूल विजन के सुनांखिक की गई है, जो नॉर्डिक पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। एंडी ने कहा, ‘द शायर एक ऐसा इलाका है, जो पूरी तरह से श्वेत दिखता है। उन्हें शायर की सीमाओं से बाहर क्या हो रहा है, इसकी खास परवाह नहीं होती, लेकिन वे किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहते।’ हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि जहां जरूरी होगा, वहां इस मुद्दे पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। ‘द हंट फॉर गोलम’ बिल्बो के जन्मदिन और फ्रोंडो के शायर छोड़ने के बीच के 17 साल के अंतराल को दिखाती है।



इस फिल्म से कहलाई थी एक्शन की रानी

मुंबई। अभिनेत्री कैटरिना कैफ 16 जुलाई, 2026 को 43 साल की हो गई हैं। फिलहाल वह बीते कुछ साल से सिनेमा से दूर चल रही हैं और अपना पूरा समय पति विक्की कौशल व बेटे विहान कौशल को दे रही हैं, लेकिन फैस उनकी वापसी की राह तक रहे हैं। इस बीच, हम आपको कैटरिना की उस फिल्म के बारे में बताएंगे जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबाही लाकर रख दी। लोगों ने अभिनेत्री को ‘एक्शन की रानी’ कहना शुरू कर दिया। यहां जिस फिल्म की बात हो रही है, उसका नाम ‘टाइगर जिंदा है’ (2017) है। यशराज फिल्मस् के स्पाई यूनिवर्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में सलमान खान मुख्य किरदार में नजर आए थे। यह ‘टाइगर’ फ्रैंचाइजी की दूसरी कड़ी है, जिसमें कैटरिना ने अपने किरदार ‘जोथा’ (पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट) के रूप में दमदार वापसी की थी।



सनी अपने बेटे राजवीर को बनाएंगे एक्शन हीरो

मुंबई। सनी देओल आगामी फिल्म ‘बटवारा 1947’ को लेकर चर्चा में हैं, जो अगले महीने 28 अगस्त को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें उनके बेटे करण देओल भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बीच, खबर है कि सनी अपने दूसरे बेटे राजवीर देओल को दोबारा सिनेमा की दुनिया में उतारने की तैयारी में हैं। इसके लिए वह 1985 में रिलीज हुई अपनी सुपरहिट फिल्म ‘अर्जुन’ का सहारा लेंगे, जिसमें राजवीर बतौर हीरो नजर आ सकते हैं। सनी अपनी फिल्म ‘अर्जुन’ का रीमेक बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनके दूसरे बेटे राजवीर मुख्य भूमिका में होंगे। राहुल रवैल द्वारा निर्देशित ये एक सामाजिक-राजनीतिक एक्शन ड्रामा थी। उन्होंने बताया कि फिल्म के अधिकार करीम मोरानी और उनके साथी सुनील (बंटी) सू्रमा के पास थे।

टीवी मसाला



‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ की डेट का ऐलान, अमिताभ ही संभालेंगे कमान

मुंबई। मेगास्टार अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18 के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वह इस पॉपुलर टिवज शो के 18वें सीजन को होस्ट करते नजर आएंगे। नए सीजन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए कंटेस्टेंट्स का मशहूर ‘हॉट सीट’ पर स्वागत किया जाएगा। यह शो बैंड प्रह्लाज जीतने के मौके के लिए उनकी जानकारी और स्किल्स को परखेगा। सोनी टीवी ने सोशल मीडिया पर कई प्रोमो शेयर कर इसके नए फॉर्मेट के बारे में भी बताया है, जो बहुत ही खास होने वाला है। इस बार कंटेस्टेंट्स को सोचना पड़ेगा। ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का प्रीमियर 10 अगस्त को होगा।

कौन बनेगा करोड़पति 18 का नया फॉर्मेट : अमिताभ बच्चन इस शो के नए सीजन के साथ फिर से वापसी के लिए तैयार हैं। शो के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के नए प्रोमो जारी किए हैं, जिनमें होस्ट अमिताभ बच्चन को रोजमर्रा की स्थितियों में दिखाया गया है। इन प्रोमो में बताया गया है कि आज जानकारी आसानी से मिल जाती है और टेक्नोलॉजी ने लोगों के सीखने का तरीका बदल दिया है, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जानकारी का समझदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसमें यह भी बताया गया है कि सोचना और सही फैसले लेना भी जरूरी है। ऐसे में कंटेस्टेंट्स को सिर्फ चीजें याद रखने के बजाय सोचने-समझने पर भी ध्यान देना होगा।

केबीसी 18 नए ट्विस्ट के साथ 10 अगस्त से होगा शुरू : ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ का प्रीमियर 10 अगस्त 2026 को होगा। चैनल ने शो के कई प्रोमो शेयर किए हैं, जिससे पता चलता है कि इस बार इसमें नया ट्विस्ट आने वाला है। पहले प्रोमो में बिग बी कहते हैं, ‘इतिहास, खेल, विज्ञान इन सबका ज्ञान इस बार केबीसी में काफी नहीं होगा। क्योंकि अब खेल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा।’ दूसरे प्रोमो में दिवंगत अमिताभ कहते हैं, ‘देखिए आज एआई ने दुनिया को बदल दिया है। ये बदलाव जो है ना रुकने वाला नहीं है जो कल तक नामुमकिन लगता था, वो आज पल भर में मुमकिन होता है। इस बदलाव ने दुनिया में हम सबको भी बदलना पड़ेगा। इसलिए केबीसी में भी हमने कुछ बदलने का प्रयास किया है, अब उत्तर देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा।’

कौन बनेगा करोड़पति 18 का तीसरा प्रोमो

तीसरे प्रोमो में वह कहते हैं, ‘आज कल जवाब जो है वो हर जगह मिलने लग गया है। आपकी जेब में भी। नहीं समझे? अरे माईसाहब आपके फोन पर। इसलिए इस बार केबीसी में हमने कुछ बदलने का प्रयास किया है, जवाब याद रखने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए जवाब आपको सोचना पड़ेगा। जी हां, सोचना पड़ेगा।’

जिस्सू ‘बहुरूपी’ में इंस्पेक्टर अयान बनकर मचाएंगे धमाल

जिस्सू सेनगुप्ता एक बार फिर पर्दे पर लौटे हैं। इस बार वह ‘बहुरूपी’ के सीक्वल ‘बहुरूपी: द गोल्डन डाकू’ में इंस्पेक्टर अयान बनर्जी का किरदार निभा रहे हैं। निर्देशक नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी (‘पोस्टो’) और ‘बाबा बेबी ओ’ जैसी फिल्में बनाने वाले के साथ जिस्सू दोबारा जुड़े हैं।

मुंबई। रथ यात्रा के खास मौके पर फिल्म से जिस्सू का पहला लुक सामने आया। इस लुक में वह पुलिस की वर्दी, एक्विपर चश्मा और मोटरसाइकिल पर सवार, एक सख्त और दमदार अवतार में दिखे। फैस को उनके इस नए अंदाज की झलक मिल गई। **शिबोप्रसाद ने फिल्म को रथ यात्रा से जोड़ा :** इस लुक ने यकीनन फिल्म के एक दमदार और रोमांचक नए अध्याय की नींव रख दी है। निर्देशक शिबोप्रसाद ने बताया कि ‘रथ यात्रा के इस शुभ दिन पर भगवान जगन्नाथ को याद करते हुए, हमने अपने इस सफर की शुरुआत कर दी है।’ यह फिल्म इंस्पेक्टर बनर्जी के इर्द-गिर्द ढेर सारे एक्शन और ड्रामा से भरपूर होने का वादा करती है। इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों में अभी से जबरदस्त उत्साह है।



गोविंदा की वापसी से पहले ओटीटी पर जरूर देखें उनकी सुपरहिट फिल्में...

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने बड़े पर्दे पर वापसी का ऐलान कर अपने प्रशंसकों को खुशखबरी दी है। उन्होंने पुष्टि की है कि वह जल्द ही फिल्म ‘रूपा’ में नजर आएंगे। उनकी वापसी को लेकर फैस के बीच जबरदस्त उत्साह है। ऐसे में नई फिल्म के रिलीज होने से पहले आइए गोविंदा की उन शानदार फिल्मों पर नजर डालते हैं, जिनका आनंद आप विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं।

‘हीरो नंबर 1’ और ‘कुली नंबर 1’

साल 1997 में आई डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म ‘हीरो नंबर 1’ में गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर, कादर खान और परेश रावल मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कॉमेडी फिल्म ‘कुली नंबर 1’ में गोविंदा के साथ-साथ करिश्मा कपूर, कारर खान, हरीश कुमार और शक्ति कपूर ने काम किया था। इस फिल्म का भी आप प्राइम वीडियो पर लुप्त उठा सकते हैं।

‘राजा बाबू’ और ‘दूल्हे राजा’

कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘राजा बाबू’ में गोविंदा के साथ-साथ करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान और अरुणा



इरानी अहम भूमिका में थे। इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। आप इस फिल्म को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। हरमेश मल्होत्रा के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म ‘दूल्हे राजा’ में गोविंदा के साथ-साथ रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर और प्रेम चोपड़ा साथ दिखाई दिए थे। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।

‘पार्टनर’

सन 2000 के दशक की गोविंदा की सबसे बड़ी हिट फिल्म ‘पार्टनर’ को डेविड धवन ने निर्देशित किया था। इसमें गोविंदा के साथ सलमान खान, कैटरिना कैफ और लारा दत्ता भी नजर आए थे। आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

‘जना नायकन’ ने मचाया तूफान की इतने करोड़ की बंपर बुकिंग

मुंबई। फिल्म प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर है। तमिलनाडु सरकार ने सुपरस्टार विजय की नई फिल्म ‘जना नायकन’ के टिकटों का अधिकतम मूल्य 190 रुपये तय कर दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि निष्पक्षता बनी रहे और टिकटों की कालाबाजारी या मनमानी कीमत वसूली पर रोक लग सके। निर्देशक एच. विनोथ द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राज्य में इसकी एडवांस बुकिंग 19 जुलाई से शुरू हो जाएगी।

एडवांस बुकिंग दुनिया भर में 4 करोड़ पार

‘जना नायकन’ फिल्म रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोर रही है। 16 जुलाई तक, इसकी एडवांस बुकिंग ने दुनिया भर में 4 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। रिलीज के दिन, दक्षिण भारत में सुबह 6 बजे से ही फिल्म के शो शुरू हो जाएंगे। वहीं, कर्नाटक के सिनेमाघरों में, जहां टिकटों की कीमतों पर कोई सरकारी पाबंदी नहीं है, वहां एक टिकट 800 से 1000 रुपये में बिक रहा है। उत्तर भारत में फिल्म की भारी मांग के कारण इसे लगभग 2000 सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। साथ ही मुंबई के मलाड और अंधेरी जैसे तमिल बहुल इलाकों में सुबह 4 बजे के विशेष शो भी रखे गए हैं।



